भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2213

गुरूवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

हिमाचल प्रदेश में रोप-वे परियोजनाएं

2213 श्री हर्ष महाजन:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम (पर्वतमाला) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित या संस्वीकृत रोप-वे परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए वर्ष-वार आवंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्वतमाला के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का/के कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है/हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) स्वीकृति प्रदान करने/पूरा होने में यदि कोई विलंब हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम (पर्वतमाला) का प्रबंधन पर्यटन मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि रोपवे सहित परिवहन अवसंरचना का विकास एक सतत प्रक्रिया है। सरकार को समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। निर्णय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के तकनीकी-वित्तीय परिणाम, आवश्यक मानदंडों की पूर्ति, संपर्कता की आवश्यकता तथा परस्पर प्राथमिकता के आधार पर लिए जाते हैं।

भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम - पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की, ताकि कठिन भू-भाग में पारंपरिक सड़कों के पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ विकल्प के रूप में पहाड़ी क्षेत्रों में अंतिम छोर तक संपर्क में सुधार किया जा सके, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सके।

इस कार्यक्रम के तहत, हिमाचल प्रदेश में एक रोपवे परियोजना अर्थात कुल्लू जिले की बिजली महादेव रोपवे को मंजूरी दी गई है, जिसकी लंबाई 2.32 किमी है और हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) पर इसकी कुल पूंजीगत लागत 226.02 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को जनवरी 2024 में मंजूरी

दी गई थी और इसका ठेका प्रदान किया जा चुका है। परियोजना के लिए वन संबंधी स्वीकृति पहले ही प्राप्त की जा चुकी है।

स्थानीय निवासियों द्वारा बिजली महादेव मंदिर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व तथा पवित्रता से संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए किए गए विरोध प्रदर्शनों के कारण जुलाई 2025 से परियोजना के क्रियान्वयन संबंधी गतिविधियाँ स्थगित हैं।

*****